

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जुलाई 2015—आषाढ़ 31, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्र. 16220-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 22 जुलाई 2015 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १२ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ४-क का संशोधन.
३. धारा १० का संशोधन.
४. धारा १४ का संशोधन.
५. धारा १६-क का संशोधन.
६. धारा १८ का संशोधन.
७. धारा २९ का संशोधन.
८. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १२ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ४ के खण्ड (दो), धारा ६ और धारा ७ के उपबंध १ अप्रैल, २०१५ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध ८ जून, २०१५ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

धारा ४-क का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४-क में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, एक बार में अधिकतम छह कलेण्डर मास की कालावधि के लिए स्थगन में वृद्धि करेगा.”

धारा १० का
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ड) के पश्चात्, उप-खण्ड (एक) में, अंक और शब्द “४ प्रतिशत की दर” के स्थान पर, अंक और शब्द “५ प्रतिशत की दर” स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का
संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (६) में, द्वितीय प्रभाग (डिवीजन) में, मद (दो) में, अंक और शब्द “४ प्रतिशत” के स्थान पर, अंक और शब्द “५ प्रतिशत” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१क ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१क झ) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट टेलीफोन, सेल्यूलर हैंड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, और इस प्रकार क्रय किए गए टेलीफोन, सेल्यूलर हैंड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.”;

(तीन) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, अंक और शब्द “४ प्रतिशत की दर से” के स्थान पर, अंक और शब्द “५ प्रतिशत की दर से” स्थापित किए जाएं.

५. मूल अधिनियम की धारा १६-क में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १६-क का संशोधन.

“(३) इस अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ के अधीन रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध दायित्वों के, जिसमें कर और ब्याज / शास्ति की बकाया शामिल है, राज्य सरकार की उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार निराकरण हेतु योजना बना सकेगी.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए “रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाई” से अभिप्रेत है—

(एक) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा संदर्भित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई, जो प्रबंधन के परिवर्तन के माध्यम से अधिग्रहण अथवा बी. आई. एफ. आर. द्वारा परिसमापन की सिफारिश के अनुसरण में परिसमापन के अधीन औद्योगिक इकाई के आधिकारिक परिसमापक से क्रय के पश्चात् पुनर्वासित किए जाने के लिए है या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ का ५४) के अधीन किसी वित्तीय संस्था, राज्य शासन के किसी निगम, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या मध्यप्रदेश वित्त निगम से क्रय की गई वृहद् / मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई;

(दो) राज्य में स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां जिनके मामले रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८५ के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के समक्ष विचाराधीन हैं और बोर्ड उनके पुनर्वास के लिए पुनर्वास योजना तैयार कर रहा है या तैयार कर ली है;

(तीन) लघु श्रेणी की औद्योगिक इकाई जिसके संबंध में उद्योग संवर्द्धन नीति के अधीन “मध्यप्रदेश लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना” स्वीकृत की गई है.”.

६. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (४) में, खण्ड (घ) में, शब्द “पचास हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् एक हजार रुपये प्रतिदिन की राशि” के स्थान पर, शब्द “पच्चीस हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् पांच सौ रुपये प्रतिदिन की राशि” स्थापित किए जाएं.

धारा १८ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (५ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा २९ का संशोधन.

“(५ग) इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब किसी व्यापारी की किसी इकाई का कारबार उसी व्यापारी की किसी अन्य इकाई में समामेलित किया जाता है, और वह प्रत्येक ऐसी इकाई के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है तो ऐसे समामेलन की तारीख को समामेलित होने वाली इकाई द्वारा धारित माल, जिसमें प्लान्ट एवं मशीनरी शामिल है, का अंतरण समामेलित इकाई में हुआ समझा जाएगा और समामेलित इकाई ऐसे समामेलन की तारीख को असमायोजित रहने वाली आगत कर रिबेट का जमा लेने का हकदार होगी.”.

निरसन तथा ८. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ३ सन् २०१५) एतद्वारा निरसित किया व्यावृत्ति. जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २०१५-१६ के लिये विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु तथा कतिपय अन्य मामलों जैसे उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार रूग्ण और बंद औद्योगिक इकाईयों के शोध्यों के समापन के लिए उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाने थे तथा अधिनियम के कतिपय अन्य उपबंधों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ३ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २१ जुलाई, २०१५.

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४ के द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी प्रस्थापना की जा रही है, जो इस प्रकार है:—

खण्ड ४ : इस खण्ड के उपखण्ड (दो) के अधीन वह रीति जिसमें आगत कर रिबेट समायोजित की जाएगी, विहित करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया जा रहा है.

उपरोक्त प्रस्थापना सामान्य स्वरूप की हैं.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

वर्ष २०१५-१६ के लिये विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री जी द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु तथा कतिपय अन्य मामलों जैसे उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार रूग्ण और बंद औद्योगिक इकाईयों के शोध्यों के समापन के लिए उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाने थे तथा अधिनियम के कतिपय अन्य प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतः महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर उपरांत दिनांक ८ जून, २०१५ को अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित कराया गया.

अब उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु विधेयक लाया जा रहा है.

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2015—श्रावण 1, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्र. 5077-213-इक्कीस-अ.(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 12 OF 2015

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) BILL, 2015

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 4-A.
3. Amendment of Section 10.
4. Amendment of Section 14.
5. Amendment of Section 16-A.
6. Amendment of Section 18.
7. Amendment of Section 29.
8. Repeal and savings.

MADHYA PRADESH BILL

No. 12 OF 2015

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) BILL, 2015

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1 (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2015.

(2) (a) The provision of cause (ii) of Section 4, Section 6 and Section 7 of this Amendment Act shall be deemed to have come into force from 1st April 2015;

(b) The remaining provisions of this Amendment Act shall be deemed to have come into force from 8th June 2015;

Amendment of Section 4-A.

2. In Section 4-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) Chereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that where such appeal is not so disposed off within the said period of stay as specified in the order of stay, the Appellate Board shall, on an application made in this behalf by the dealer and on being satisfied that the delay in disposing of the appeal is not attributable to the dealer, extend the stay for a maximum period of six calendar months at a time."

Amendment of Section 10.

3. In Section 10 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (e), in sub-clause (i), for the words and figure "the rate of 4 percent", the words and figure "the rate of 5 percent" shall be substituted.

Amendment of Section 14.

4. In Section 14 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), in clause (a), in sub-clause (6), in second division, in item (ii), for the figure and word "4 percent", the figure and word "5 percent" shall be substituted;

(ii) after sub-section (1AH), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1AI) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases telephone, cellular hand set and phablet, pan masala and gutka (without tobacco) as specified in Part-III A of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax and sells the telephone, cellular hand set and phablet, pan masala and gutka (without tobacco) so purchased within the State of Madhya Pradesh, he shall claim and be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.";

(iii) in sub-section (5), in clause (a), in sub-clause (i), for the words and figure "at the rate of 4 percent", the words and figure "at the rate of 5 percent" shall be substituted.

Amendment of Section 16-A.

5. In Section 16-A of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or the Acts repealed by this Act, the State Government may make a scheme to liquidate the liabilities

including arrears of tax and interest / penalty, under the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958, the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994, the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 administered by the Commercial Tax Department, against the sick or closed industrial units, in accordance with the provisions of the Industrial Promotion Policy of the State Government.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, "the sick or closed industrial unit" means—

- (i) the large and medium scale industrial units referred by the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for being rehabilitated after acquisition/ takeover through change of management or by way of purchase from official liquidator of industrial unit under liquidation pursuant to recommendation for winding up by BIFR or the large / medium scale industrial units purchased under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002), from a financial institution, a State Government Corporation, Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation or Madhya Pradesh Financial Corporation;
- (ii) the large and medium scale industrial units situated in the State, whose cases are under consideration before the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 and the Board is preparing or has prepared rehabilitation scheme for their rehabilitation;
- (iii) the small scale industrial unit in respect of which "Madhya Pradesh Small Scale Industries Revival Scheme" under the Industrial Promotion Policy has been sanctioned."

6. In Section 18 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (d), for the words "a sum of rupees fifty per day for first thirty days of default and thereafter a sum of rupees one thousand per day, subject to a maximum of rupees fifty thousand", the words "a sum of rupees fifty per day for first thirty days of default and thereafter a sum of rupees five hundred per day, subject to a maximum of rupees twenty five thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 18.

7. In Section 29 of the principal Act, after sub-section (5B), the following sub-section shall be inserted, namely :—

Amendment of Section 29.

“(5C) Notwithstanding anything to the contrary contained anywhere else in this Act, when the business of a unit of a dealer is amalgamated into another unit of the same dealer and he holds separate registration certificate for each of such units, the goods including plant and machinery, held by the amalgamating unit on the date of such amalgamation shall be deemed to have been transferred to the amalgamated unit and the amalgamated unit shall be entitled to take credit of input tax rebate, which remains unadjusted on the date of such amalgamation.”.

8. (1) The Madhya Pradesh Vat (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 3 of 2015) is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to implement the tax proposals contained in part II of speech delivered by the Finance Minister while presenting the budget in the Legislative Assembly for the year 2015-16, and to make provisions for certain other issues like liquidation of dues of sick and closed industrial units in accordance with the provisions of Industrial Promotion Policy, appropriate amendments were to be made in the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and few other provisions of the Act were to be rationalized.

2. As the matter was urgent and the Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 3 of 2015) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature without any modification.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 21st July, 2015

JAYANT MALAIYA
Member-in-Charge.